''वाइब्रैंट गुजरात'' की तर्ज पर राजस्थान में भी होगा उद्योग समिट: भजनलाल शर्मा

जे.ई.सी.सी. सीतापुरा में इंडिया स्टोनमार्ट के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की

जे.ई.सी.सी. सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोनमार्ट के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया।

- उद्यमियों को सभी क्लियरैंस एक ही छत के नीचे देने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम प्रभावी रूप से लागू करेंगेः मुख्यमंत्री
- अगले 5 साल में पत्थर उद्योग में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने का विभाग ने संकल्प लिया हैः कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ''वाइब्रैंट गुजरात'' की तर्ज पर राजस्थान में भी उद्योग समिट का आयोजन किया जायेगा। प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा उद्यिमयों को विभाग से जुड़ी सभी क्लियरेंस एक ही छत के नीचे देने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम को अब प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से आव्हान किया कि वे राजस्थान में निवेश के लिए आगे आएं, सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने यह बात गुरूवार को जे.ई.सी.सी. सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोनमार्ट के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोनमार्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया व प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की गई है। इस भव्य मंदिर में राजस्थान का गुलाबी पत्थर तथा मार्बल उपयोग में लिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। राजस्थान के पत्थर उद्योग को विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने में इंडिया स्टोनमार्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। पत्थर के उद्योग से राज्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट को रिसाइकल करना बहुत आवश्यक है। इस तरह के वेस्ट को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसा की वर्तमान में किशनगढ़ मार्बल की स्लरी का उपयोग उद्योग के रूप में किया गया।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगले 5 साल में पत्थर उद्योग में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने का विभाग ने संकल्प लिया है। उन्होंने उद्यिमयों की तारीफ करते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को कारीगरों द्वारा ही साकार किया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्यिमयों को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, जिससे उद्यिमयों को राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल मिल सके। राज्य में पत्थर उद्योग के साथ नव्यकरणीय ऊर्जा, जवाहरात, खनन सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा और अधिक विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंटीरियर डिजाइनिंग, लैण्डस्केपिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यिमयों, लाइफटाइम अचीवमेन्ट अवॉर्ड से उद्यमी किरण जे. त्रिवेदी तथा यशवंत कुमार शर्मा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इंडिया स्टोनमार्ट निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल, खान सचिव आनंदी, रीको के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद थे।

हिमाचल में भारी हिमपात से 6 नेशनल हाइवे अवरूद्ध

शिमला, 01 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात के कारण काफी संख्या में सड़कें अवरुद्ध होने से कई इलाकों का सम्पर्क टूट गया है और इसके कारण प्रदेश में 241 सड़कें अवरुद्ध हैं, 677 ट्रांसफार्मर ठप है तथा कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है।

शिमला जिला के ऊपरी इलाकों का भारी बर्फबारी से राज्य मुख्यालय से सम्पर्क कट गया है।

कुफ़री, फागु, नारकंडा, चौपाल तथा खड़ापत्थर जाने वाली सड़कें बंद पड़ गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फ़बारी से छह नेशनल हाइवे सहित 241 सड़कें अवरुद्ध हैं। साथ ही 677 ट्रांसफार्मर ठप होने से कई जगह बिजली गुल हो गई है।

सुबीर कुमार उच्च व तकनीकी शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव बने

- 17 आई.ए.एस. के तबादले, तीन को अतिरिक्त प्रभार।

जयपुर, 1 फरवरी (का.सं.)। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के 17 अफसरों के तबादले किये हैं। वहीं तीन को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।

सुबीर कुमार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रमुख शासन सचिव व रश्मि गुप्ता को गृह सचिव के पद पर लगाया है।

इसी प्रकार भवानी सिंह देथा को आयोजना, आयोजना (जनशक्ति और गजेटियर्स) में प्रमुख शासन सचिव, विकास सीतारामजी भाले को पशुपालन, मत्स्य एवं गौ-पालन विभाग में प्रमुख शासन सचिव, डॉ. पृथ्वीराज को श्रम, कारखाना और बॉयलर निरीक्षण विभाग में शासन सचिव, गौरव गोयल को राज्यपाल का सचिव, पूर्ण चन्द्र किशन को कौशल और उद्यमिता व रोजगार विभाग में शासन सचिव, विजयपाल सिंह को गृह विभाग में शासन सचिव, विश्राम मीणा को जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में निदेश एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, मुकुल शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में संयुक्त शासन सचिव, नेहा गिरी को राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, अनुपमा जोरवाल को राजस्थान पर्यटन विकास निगम में प्रबंध निदेशक, सुरेश कुमारी ओला को स्थानीय निकाय विभाग में निदेशक और पदेन संयुक्त शासन सचिव, प्रियंका गोस्वामी को स्टेट हैल्थ एश्योरेंश एजेन्सी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किशोर कुमार को सिविल एविएशन और उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग एवं कंट्रोलर, सर्किट हाउस एवं नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्टेट मोटर गैराज विभाग में निदेशक, महेन्द्र खड़गावत को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में निदेशक, गिरधर को ऊर्जा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया गया है।

वहीं भवानी सिंह देथा को युवा मामले एवं खेल विभाग में प्रमुख शासन सचिव, राजन विशाल को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जनअभियोग निराकरण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभा में शासन सचिव तथा मुकुल शर्मा को राजसीको का प्रबंध निदेशक और ग्रामीण अकृषि विकास अभिकरण में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

हाई कोर्ट ने वकीलों से राय मांगी

- क्या महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी उचित है?

जयपुर, 1 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव बाद नई सरकार के गठन के बाद भी अब तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं करने से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि दो माह का समय बीतने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं होना ठीक नहीं है। अदालत ने इनकी नियुक्ति के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा पांच फरवरी तक बताने को कहा है। अदालत ने सवाल खडा किया है कि क्या महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी करना न्यायोचित है या नहीं? अदालत ने इसके लिए वकीलों से अपने सुझाव अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यूडीएच विभाग में अभियंताओं की वरिष्ठता से जुडे मामले में रविन्द्र प्रकाश की याचिका में सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा से पूछा की महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी पर बार एसोसिएशन का क्या रुख है। इस पर प्रहलाद शर्मा ने कहा की महाधिवक्ता की नियुक्ति संवैधानिक तौर पर गवर्नर ही करते हैं। इनकी नियुक्ति नहीं होने से राज्य सरकार की ओर से कोर्ट केसेज में प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आमजन व पक्षकारों को न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। यह मामला जनहित से जुडा हुआ है। इसलिए इसे खंडपीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई पांच फरवरी को तय करते हुए वकीलों से इस संबंध में अपने सुझाव पेश करने को कहा है।

सत्ररहवां ''लिटरेचर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गोखले और विलियम डैरिम्पल तथा इसके तेजस्वी आयोजक संजय रॉय ने अपने अनुभव एवं दृढ़ता के साथ इस आयोजन का मार्गदर्शन किया है। दूसरा, जैसा कि बताया गया है, पर स्पष्ट नहीं है कि क्या जे.एल.एफ. जैसे कॉर्निवल आज के ''इन्सट्रैट कॉफी'' कल्चर में पढ़ने की आदत डालने में मददगार हो सकते हैं अथवा नहीं। शायद, इतना ही पर्याप्त है कि जे.एल.एफ. का आयोजन राजस्थान में पर्यटन को इतना अधिक प्रोत्साहित करता है, जितना राज्य का पर्यटन विभाग पूरे साल में भी नहीं कर सकता।''

यह बयान, राज्य को गौरवान्वित कर सकता है, क्योंकि जे.एल.एफ. यदि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करता है तो यह कम से कम उसे हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करता।

नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अपने आलोचनात्मक रूख के लिए जाने जाने वाले पत्रकार रवीश कुमार की कमी खल रही है और बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर, अरून्धति रॉय व बरखा दत्त को स्टार वक्ताओं की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। संभवत: इसलिए कि पहले भाग ले चुके वक्ताओं को प्रति वर्ष बुलाना ना तो जरूरी है ना ही वांछित।

झारखंड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिभाषा है, क्या आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतना ज्यादा डरते हैं।''

मासलपुर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सलाह दी है। मासलपुर क्षेत्रीय वन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि मासलपुर के सकलूपुरा और रूंधपुरा के पास जंगलों में ग्रामीणों द्वारा टाइगर का मूवमेंट होने की सूचना दी गई। वन विभाग के वनपाल विकास कुमार, रामनिवास मीणा, वनपाल शिवांग कुमार शर्मा, वनरक्षक दर्शन, वनरक्षक नंदकिशोर, वनरक्षक जालम सिंह सहित टीम के सदस्यों ने मासलपुर के जंगलों में टाइगर के मूवमेंट की सूचना पर ट्रेकिंग के लिए अभियान शुरू किया। सकलूपुरा से मरदई की ओर जाते हुए पैंथर के पगमार्क मिले हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

सोरेन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नयी दिल्ली, 01 फरवरी। उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोरेन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए गुरुवार को उनकी गुहार स्वीकार करते कहा कि, वह शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिन बाद गुरुवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की।

- मुख्य न्यायाधीश ने सोरेन की शीघ्र सुनवाई की याचिका स्वीकार की।

पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी ने सोरेन की याचिका पर यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि, उनके गिरफ्तारी के तरीके से देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

याचिकाकर्ता सोरेन के वकील ने कहा कि, यह एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया।

सोरेन के वकील ने दावा किया कि, ईडी की ओर से याचिकाकर्ता को बुधवार शाम पांच बजे गिरफ्तार किया गया।

राहुल ने मालदा से अपनी यात्रा शुरु की

मालदा, 01 फरवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती मालदा जिले से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की।

गांधी की कार में एक दिन पहले दोपहर में बिहार से इस राज्य की सीमा पार करते समय तोड़फोड़ की गई थी।

वित्त मंत्री सीतारमन ने देश की इकॉनमी की...

- वित्त मंत्री का कहना है, आमदनी में भारी वृद्धि तभी संभव है, जबकि देश की इकॉनमी की ग्रोथ 11 प्रतिशत हो, यह अंसभव नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन ने यह ''डबल डिजिट'' ग्रोथ रेट कई सालों तक बरकरार रखी है।

रक्षा बजट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा लगाने का वादा किया है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि, राजकोषीय आंकड़े अधिक यथार्थवादी दिखते हैं लेकिन, भारत को ऋण वहन क्षमता के संबंध में अभी भी महत्वपूर्ण सुधार करने की जरुरत है।

विशेषज्ञों ने अनेक ''सतत विकास केन्द्रित'' बजट की सराहना की है तथा आशा करते हैं कि, लोकसभा के जुलाई सत्र में पूर्ण बजट पेश कर दिया जाएगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जी.डी.पी. के 5.1 प्रतिशत तक रह सकता है।

ऋण जरूरतों की अनुमानित कमी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि, अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल व शुद्ध ऋण जरूरतें क्रमश: 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहेंगी। यदि वर्तमान वित्त वर्ष में भी ऋण जरूरतें कम रहती हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

चूंकि सरकार की ऋण जरूरतें भी कम रह सकती है और ब्याज दरें भी यथास्थिति रहेंगी, इसलिए वित्त मंत्री की घोषणाओं की प्रतिक्रिया में भारत के बॉण्ड मार्केट में नरमी आयी है।

यह तभी संभव हो सकता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक राजस्व प्राप्तियों के साथ अपना उच्च स्तर बरकरार रखे और सरकार को पूंजी व्यय में वृद्धि की अनुमति देने के साथ ही बजट घाटे को जी.डी.पी. के 5.1 प्रतिशत तक रोके रखे।

उच्च आर्थिक वृद्धि के अनुमान के साथ ही वित्त मंत्री ने सार्वजनिक पूंजी व्यय में 11,11,111 करोड़ यानी की 11 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की घोषणा की है। यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि 11 के आंकड़े के प्रति वित्त मंत्री के आकर्षण में पूर्णता के कोई रहस्यमय गुण छिपे हुए हैं।

बजट के गणित को देखते हुए मोटे तौर पर यह सत्य है कि वित्त मंत्री की इच्छाएं आसानी से पूरी हो सकती थीं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट दहाई के अंक तक पहुंच जाती है खास कर 11 के जादुई आंकड़े तक या उसके करीब। यह दावा बहुत लम्बा चौडा है पर पड़ौसी चीन कभी यह ग्रोथ रेट हासिल कर चुका था।

हालिया रूझानों को देखते हुए यह उम्मीद करना अनुचित भी नहीं है क्योंकि भारत तेजी से बढ़ रहा है जब शेष विश्व, खासकर हमारे बड़े पड़ौसी चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है।

वर्तमान अंतरिम बजट की अन्य विशेषताओं की जहां तक बात है वित्त मंत्री ने इसे राजनीतिक रंग दिया जो प्रत्याशित भी था। वैसे बजट में निर्मला सीतारमन ने विभिन्न वोट बैंक्स को संतुष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने जनता के चार वर्गों को ध्यान में रखा गरीब, युवा महिला और किसान।

सभी सरकारें गरीबों के हित में काम करती हैं। वर्षों पहले इंदिरा गांधी ''गरीबी हटाओ'' कार्यक्रम चलाया था। और अभी भी गरीब सरकार की सूची में सर्वोपरि है। वर्तमान सरकार भी अपवाद भी नहीं है।

उन्होंने वर्ष 2014 के बाद से ढाई करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से स्तर से ऊपर लाने का श्रेय लिया है। उन्होंने कहा कि, सरकार गरीबों को संपूर्ण विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए, अधिकार की राजनीति से दूर जाना चाहेगी। उन्होंने दावा किया है कि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नीतियों से अद्भुत काम किया है।

अब जबकि आम चुनाव कुछ महीने ही दूर हैं तो बजट की लोकलुभावन अपील का दूसरा मुद्दा ''महिला अधिकार'' है। क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए महिला अधिकारों के लिए नीतियों का अनुसरण करना, उचित रणनीति है।

वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बेहतर स्कूल और शिक्षा प्रदान करने की पहल का जिक्र किया है। उन्होंने नए आई.आई.टी., आई.आई.एम. बिजनेस स्कूल और अन्य निकायों की स्थापना के बारे में जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त, युवाओं को बेहतर कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

यद्यपि, वित्त मंत्री ने युवा रोजगार रूझानों और योजनाओं के संदर्भ में विवरण नहीं दिया है, क्योंकि शिक्षित युवा बेरोजगारी एक बड़ा विषय है तथा बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को मनचाही नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं।

निसंदेह, यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है अपितु तेजी से विकसित हो रहे चीन को भी, युवा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि चीन में, युवा बेरोजगारी की बढ़ती संख्या के कारण, युवा बेरोजगारी पर आंकड़े देना बंद कर दिए हैं।

किसान हमेशा से सभी सरकारों के लिए, एक महत्वपूर्ण वर्ग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि उत्पाद व्यापार मंच संस्थान ने, किसानों को सीधे बाजार में जाने तथा बेहतर कीमत पाने में मदद की है। अनिश्चितताओं से निपटने के लिए फसल बीमा और अन्य सुविधाओं के लिए बेहतर योजानएं भी शुरु की गई हैं।

इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वित्त मंत्री ने अपना बजट वर्तमान मोदी सरकार के सुदृढ़ आर्थिक प्रबंधन की उपलब्धियों के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रुप में तैयार किया था।

वास्तव में, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने दम पर बढ़ने और विकसित होने का लचीलापन है, बशर्ते सरकार, अर्थव्यवस्था और इसकी लय को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम न करे। ग्रोथ रेट में कमी आना अधिकांशत: सरकार की कारगुजारी होती है और ऐसा वे अनजाने में कर देती हैं।

सोरेन की रिमांड पर फैसला शुक्रवार को

रांची, 01 फरवरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी में कमरा नंबर एक में गुरूवार रात बितानी पड़ेगी।

ईडी कोर्ट में पेशी के बाद सोरेन को आज सीधे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार ले जाया गया। सोरेन को आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि, 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने इन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद इनकी पेशी ईडी कोर्ट में की गयी थी।रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शुक्रवार को अदालत फैसला सुनाएगी।

इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायक गुरूवार को रांची से हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे लेकिन खराब मौसम के कारण चार्टर्ड प्लेन को उडने की इजाजत नहीं मिल पाई।

'दो भारत, साथ-साथ रह रहे हैं अपने...

- राजन ने कहा, रेवड़ी बांटना सच्चा विकास नहीं है, सच्चा विकास है गरीब को अच्छा रोजगार देना।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अच्छी नौकरी हो, ये हम कैसे कर सकते हैं।'' सरकार से यह सवाल ज़रुर पूछना चाहिए और एक समाज के रुप में हमें ये प्रश्न पूछने चाहिए और समाधान ढूंढने चाहिए।''

रघुराम राजन ने अपनी पुस्तक, ''ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमैजिनिंग द इकोनॉमिक फ्यूचर'' में आर्थिक विकास के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए, रघुराम राजन ने एक ब्लू प्रिंट पेश किया है, जिसके बारे में दोनों लेखकों का मानना है कि, दोनों भारत करीब आ सकते हैं और समग्र विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

इसके लिए शासन तंत्र, प्रक्रियाओं तथा नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वन के विकेन्द्रीकरण (डीसैन्ट्रलाइज़ेशन) की आवश्यकता होगी। यह विकेन्द्रीकरण केन्द्र से राज्यों और राज्यों से जिलों तक होना चाहिए, ताकि ये सभी क्षेत्र उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों, जिससे वहाँ विकास में तेजी आए।

उन्होंने कहा, ''विशाल इमारतें बनाना पर्याप्त नहीं है, हालांकि इससे नौकरियाँ भी पैदा होती हैं। इसके बजाय, सैकड़ो -हजारों नौकरियाँ पैदा करने की ज़रुरत है वो भी अच्छी नौकरियाँ। इसके अलावा शिक्षा के निर्माण पर जोर देने, लोगों को बेहतर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए उनका कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है तथा ऐसा वातावरण पैदा करना, जिसमें हर एक व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्र निर्माण में अधिक योगदान दे रहा हो।''

आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर ने आगे कहा कि, पिछले 30 सालों में, भारत औसत 6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, लेकिन 2004 से 2014 के दौरान 9 से 10 प्रतिशत के बीच, एक दशक उच्च वृद्धि हुई और अगर देश को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो अगले तीन दशकों तक भारत को इसी प्रकार की वृद्धि की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केन्द्रीय बजट पर टिप्पणी करने के लिए माफी मांगते हुए रघुराम राजन ने कहा कि, वो अपनी किताब पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, किताब अर्थशास्त्र पर है लेकिन केवल अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए है, आसान भाषा में हमने कई उदाहरण देने का प्रयास किया है जिन्हें समझना आसान है। हमें उम्मीद है कि, बहुत लोग इसे पढ़ेंगे और साथ में अर्थशास्त्र को भी समझेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि ''बेसिक कॉन्सैप्ट्स'' समझने के लिए गहरे अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक का हिन्दी व तमिल में अनुवाद भी उपलब्ध है।

त्रुटिहीन हिन्दी में बोलते हुए, पूर्व आर.बी.आई. गवर्नर ने कहा, ''हमारी आर्थिक समस्याएं हल करने के लिए हमने वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करने की कोशिश की है।

समाधानों में से एक यह है कि, लोगों के लिए अपेक्षित संख्या में गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ पैदा की जाएं, सर्विस प्रोवाइडर और निर्माता जो नौकरियाँ लाते हैं उनके लिए लोगों में कौशल पैदा किया जाए। हमने किताब में, यह ''कैसे करें'' इस पहलू पर प्रकाश डाला है।

एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, ''अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, और पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं होते हैं, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे युवाओं के कारण अत्यधिक सामाजिक हानि होने की संभावना है।

देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, और हर कोई सरकारी नौकरी की लालसा कर रहा है, क्योंकि उन्हें ही अच्छी नौकरी माना जाता है।

इसलिए हमें निजी क्षेत्र में नौकरियों की और अधिक संभावनाएं पैदा करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता और अत्यधिक महत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने का है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि, छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया, तो हम अपने प्रयासों में असफल होते रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि, यदि स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए तो बहुत कुछ होगा और इसे मिशन मोड में किया जाना चाहिए। तमिलनाडू और दिल्ली में भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है।

विपक्ष ने बजट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वो व्यर्थ है, भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके शर्मनाक रिकार्ड बनाया है। जो कभी भी नहीं टूटेगा क्योकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय है यह भाजपा का विदाई बजट है।''

नेशनल कॉन्फ्रेन्स के फारूख अब्दुल्लाह ने कहा कि वास्तविक बजट जुलाई में आएगा। हमें उम्मीद है कि लोगों को फायदा होगा, पर्यटन व उद्योग में वृद्धि होगी। देश का विकास होगा। सांसद दानिश अली ने कहा बजट में कुछ भी नया नहीं है। द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है लोग पहले से ही निराश हैं। आज सांसद स्वाति मालीवाल ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि देश में महंगाई व बेरोजगारी अपने चरम पर है।

तीये की बैठक

हमारी पूजनीय

श्रीमती इन्दर कँवर

दिनांक 31 जनवरी 2024 को अपनी सांसारिक यात्रा सम्पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं।
तीये की बैठक दिनांक 2 फरवरी 2024 को सांय 3:00 से 4:00 बजे तक निज निवास पर होगी।

शोकाकुल

डॉ. अमर सिंह राठौड़ (पति)

निदेशक (सेवानिवृत्त) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
अनु- राजेन्द्र (पुत्री- दामाद), रचना- राजेश (पुत्री- दामाद),
उत्कर्षा, अभिषेक, शानवी (दौहित्र, दौहित्री)।
मो.- 9829036513

निवास:
एस- 134, गेट नं. 4, महावीर नगर, गोपालपुरा पुलिया के पास, टोंक रोड, जयपुर।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्पाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908